डेवलपमेंट द्वारा काफी ध्यान दिया गया है और अपने एक अध्ययन में इनके उत्पादन को बढ़ाने एवं अनुसंधान पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अनुसार अनुसंधान की बेहतर प्रक्रिया विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अत: माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वे इन जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने तथा अनुसंधान की कार्यवाही को विकसित करने के लिए बहुराष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र की दवा कम्पनियों से अनुबंध करा करके ही उसे लाइसेंस आदि तथा अन्य सुविधायें प्रदान करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो उससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करें एवं सख्ती बरतने पर गौर करें।

(vii) Need for a legislation to provide Compensation to those kept in jails for a period larger than pronounced by courts

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष जी, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विभिन्न जेलों में सजा-अवधि से काफी अधिक दिनों तक कैदियों के रखे जाने के समाचार मिल रहे हैं। काफी निर्दोष लोगों को भी पैसा एवं पैरवी के कारण जेल की यातनायें सहनी पड़ती हैं। संसार के दूसरे भागों की तुलना में भारत में आदमी एवं जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। गरीब का जीवन तो कीड़े एवं जानवर से भी बदतर है। जिस मुकदमे में एक दिन की न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाती उसी मुकदमे में कई सालों तक जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इन कुव्यवस्थाओं के तीन कारण हैं। एक तो महंगा न्याय तथा दूसरा न्याय मिलने में विलम्ब। तीसरा कारण हैं सरकार को कोई हरजाना नहीं देना पड़ता है।

अत: सरकार से मांग है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना वजह जेल में रखा जाता है या सजा की जितनी अवधि है उससे अधिक अवधि तक रखा जाता है तो सरकार उस व्यक्ति को हरजाना दे। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक भी प्रस्तुत करे। सरकार से यह भी मांग है कि वह मुफ्त न्याय एवं जल्द न्याय की व्यवस्था करें।

(viii) Need for strict implementation of Constitutional provisions for reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Schools/ Colleges and jobs.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष जी, देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए घोषित सरकारी आरक्षण नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में घोषित आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। सरकारी सेवाओं में वर्ग एक दो, तीन और चार के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस पर दोहरी मार पड़ती है। आम लोगों की धारणा है कि उसे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और वस्तुस्थिति यह है कि उसे तथाकथित विशेष सुविधायें नहीं मिल रही हैं। शिक्षा में आरक्षण प्रवेश के लिए है न कि परीक्षा के मूल्यांकन में है। प्रवेश में आरक्षण का कारण उसकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विषम स्थितियां हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश का आधार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इसके लिए भी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही तो कारण है। स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण नहीं किया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति को पूरे तौर पर क्रियान्वित करने के लिए सक्षम कानून बनाया जाये।

(ix) Damage to sugarcane crop by insects in various parts of the country and need for immediate measures to save the crops.

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अंतर्गत मैं सदन और

[श्री रामलाल राही]

सरकार का ध्यान गन्ने की फ़सल में लगने वाले रोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह रोग इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की हजारों हैक्टेयर गन्ने की खड़ी फसलों में ग्रेब अथवा हापर आदि नाम के कीड़े गन्ने की पत्तियों को खाकर पूरी की पूरी फसलें नष्ट करते जा रहे हैं। कीट-नाशक दवाइयां इन रोगों को रोक पाने में असफल रही हैं। परिणामस्वरूप गन्ने के उत्पादन में गिरावट आना प्रारम्भ हो गई है। वर्ष 1982-83 में देश में जहां गन्ना लगभग 189 मिलियन टन हुआ था, वहीं सन् 1983-84 में 25% के लगभग कम हो गया है। गन्ना शोध संस्थान गन्ने की तरह-तरह की किस्में तो बना रहा है, बढ़ा रहा है, परन्तु गन्ने में लगने वाले रोगों की रोकथाम करने के उपाय करने में असफल रहा है।

उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई आदि जिलों में भी गन्ने की हजारों हैक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं। मैं स्वयं जा कर देख आया हूं। जहां यह रोग गन्ने की फसलों में लगा है वहीं अन्य खरीफ की फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की फसलों की पत्तियों को खाता व नष्ट करता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र के किसान हतोत्साहित होकर गन्ने की फसलों को बोना और कम कर देंगे। परिणाम-स्वरूप चीनी के आयात की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। किसानों में व्यापक रोष है। सरकार से मांग है कि अविलम्ब इस रोग के निदान के उपाय किये जायें। युद्धस्तर पर प्रभावी दवाइयों का छिड़काव कराकर फसलें बचाई जायें और गन्ना शोध संस्थान गन्ने में लगने वाले रोगों के रोकने के उपाय पर प्रभावी कदम उठावे।

(x) Need to declare Purnea district of Bihar as famine-stricken

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : मान्यवर, नियम 377 के अन्तर्गत मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र पुर्णिया की ओर दिलाना चाहती हूं जो बाढ़ और वर्षा के कारण तबाह हो रहा है। शहर हो या देहात, लोग बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। शहर के कोई भी मुख्य स्थान पर लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। किसानों के लिए तो विषम समस्यायें बनी हुई हैं। जब मैं पिछली बार गर्मी के मौसम में अपने क्षेत्र के दौरे पर गई थी तो बजाए गर्मी से परेशान होने के वर्षा से कठिनाई का सामना करना पड़ा था और अभी की तो हालत ही कुछ और है। गर्मी के मारे सारी फसल नष्ट हो चुकी हैं। किसान तैयार फसल खेतों से घर नहीं ला सके। अभी पानी का जमाव इतना है कि लोग 5 प्रतिशत से ज्यादा धान नहीं पा सकेंगे। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिहार सरकार से कहा जाय कि जल्द से जल्द वहां अकालग्रस्त इलाका घोषित किया जाये जिससे किसान, मजदूर राहत की सांस ले सकें। मेरा एक निवेदन और है कि 84-85 का खजाना माफ कर दिया जाये तथा रबी फसल के लिए गरीब किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा बीज अनुदान के रूप में दिया जाए।

(xi) Need to improve the working of telephone exchanges in Vidisha Parliamentary Constituency

SHRI PRATAP BHANU SHARMA (Vidisha) : Under Rule 377, I make the following statement :

The telephone system in Vidisha Parliamentary Constituency is totally defunct and defective. Subscribers are experiencing day to day difficulties in local and trunk calls. Most of the exchanges are either defective or out of order due to poor maintenance and faulty equipments. I would like to draw the attention of the Communications Minister to the following points :

1. Vidisha auto exchange is not working satisfactorily due to various technical faults and ineffective maintenance.

2. Vidisha Trunk Exchange is connected with Indore-TAX by means of Operator Trunk Dialling Circuit (OTD). But most of the time the TAX system remains out of order resulting in poor trunk services to the subscribers of Vidisha District.